माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ

*देवेन्द्र सिंह**

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा नीतियों संवैधानिक प्रावधान सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की वजह से आज हम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। और अब भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसके लिए सर्वशिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी हैं तथा उनका समायोजन कैसे किया जा सकता है ताकि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। इस प्रकार इस पत्र में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सर्वव्यापीकरण मुद्दों पर प्रकाश डाला जा रहा है।

परिवर्तन एवं संवर्द्धन एक अनिवार्य प्राकृतिक परिघटना है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्र विशेष की प्रगति एवं समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक अपनी संभावनाओं की सर्वोच्चता के कितने निकट हैं। नागरिकों की अपनी संभावनाओं की सर्वोच्चता पर प्रतिष्ठित करना गुणात्मक शिक्षा प्रणाली का कार्य है क्योंकि सबका संवर्द्धन एवं विकास मनुष्य करता है लेकिन मनुष्य के अंतर्गत मानवीय गुणों का विकास शिक्षा करती है क्योंकि शिक्षा आंतरिक एवं परिभाषात्मक रूप से मूल्योन्मुखी है। यह व्यक्ति को विशिष्ट दिशा की तरफ अग्रसर करती है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय दर्शन के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय शैक्षिक तंत्र सृजित करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक तंत्र जितना ही सुदृढ़ एवं आधुनिकतम प्रणाली उपागमों पर आधारित होगा उतना ही वह राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति विभिन्न संस्कारों के माध्यम से अपने शरीर, मन और आत्मा के तीनों पक्षों का समन्वित विकास कर समाज एवं राष्ट्र का उपयोगी नागरिक बनता है। इसीलिए शिक्षा को जीवन की प्रयोगशाला माना गया है (मीडिया मीमांसा-2008)।

*रीडर, शिक्षा संकाय, सतीश चन्द्र कॉलेज, बलिया (उ.प्र.).

शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है राष्ट्र निर्माण हेतु सभ्य एवं सुसंस्कृत चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा छात्रों में जिज्ञासा पैदा करे और प्रश्न करना सिखाए। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों के लिए प्रश्न का कोई स्थान ही नहीं है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माण से दूर होती जा रही है एवं अपेक्षाकृत सैद्धांतिक व सूचनात्मक होती जा रही है। उसका समाज व उसकी समस्याओं से संबंध-विच्छेद सा हो गया है। शिक्षा प्रणाली में समग्रता का अभाव है। इसे कई खंडों में विभाजित कर दिया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा जैसे कई स्तर बन गए हैं। एक तरफ माध्यमिक शिक्षा के प्रति सरकार का दृष्टिकोण तटस्थ है, वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो रहा है एवं उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है। निष्कर्षत: माध्यमिक शिक्षा की कीमत पर प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा का विस्तार हो रहा है एवं माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के बीच सशक्त माध्यम न होकर मध्यम श्रेणी की भूमिका निर्वाह कर रही है। इन संदर्भों में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता हेतु अनिवार्यत: सर्वव्यापीकरण सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है।

माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के परिणाम से उत्साहित होकर केंद्र सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय सर्व शिक्षा अभियान के मॉडल पर माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मकता हेतु माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण (Universalisation of Secondary Education) के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) हेतु सिद्धांतत: सहमत हो गए हैं। सार्वजनिक व्यय एवं वित्त समिति (Expenditure Finance Committee) ने सर्वव्यापीकरण हेतु मिशनरी दृष्टिकोण के साथ प्रस्ताव की पुष्टि कर दी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रस्ताव की मूल विशेषताएँ अधोलिखित हैं—

(क) 15 एवं 16 वर्ष तक के सभी बालकों को 2017 तक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध, प्राप्य एवं देना सुनिश्चित करना।

(ख) 2020 तक 15 एवं 16 वर्ष तक के सभी बालकों का सार्वभौमिक ठहराव सुनिश्चित करना।

(ग) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अनुमानित लागत रु. 42705 करोड़ रूपये होगी, जिसमें से 34164 करोड़ रूपये केंद्र सरकार वहन करेगी।

(घ) 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव सुनिश्चित करने हेतु कुल लागत रु. 54000 करोड़ अनुमानित है।

(ड.) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 किमी. के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना।

(च) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसँख्यकों एवं अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा हेतु विशेष प्रावधान होना।

(छ) सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विलय (दि हिन्दू-2008)।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 2 लाख अतिरिक्त शिक्षक आवश्यक होंगे। वर्तमान में 1:32 के शिक्षक-छात्र अनुपात से कुल 10.82 लाख शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। लेकिन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) द्वारा 1:30 शिक्षक-छात्र अनुपात के दृष्टिकोण से 72000 शिक्षकों के चयन करने होंगे। इसके अतिरिक्त 53.10 लाख अतिरिक्त नामांकन हेतु 1.77 लाख अतिरिक्त शिक्षक वांछित होंगे। 2005-06 के लिए 58.86% माध्यमिक विद्यालय निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं जिसमें से 31.08% निजी वित्तविहीन विद्यालय हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशनरी दृष्टिकोण के साथ एक सकारात्मक कदम है जो माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मकता से प्रत्यक्षत: संबंधित है।

चुनौतियाँ

माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ अधोलिखित हैं—

(क) प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में बालकों के सकल नामांकन दर में काफ़ी विषमता है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए यह दर 95% है, उच्च शिक्षा के लिए 10.3% है वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए यह दर 36% है अर्थात् 60% से अधिक छात्र माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं (वू, कौल एंड शंकर, 2005)।

(ख) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर आवंटित बजट प्रावधान विभेदकारी है। जहाँ शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा पर 50% खर्च किया जा रहा है वहीं माध्यमिक शिक्षा पर 30% एवं उच्च शिक्षा पर 13% ही खर्च किया जा रहा है (तिलक, 2004)।

(ग) कोठारी आयोग (1964-66) ने स्पष्ट सुझाव दिया था कि शिक्षा पर आवंटन का 2/3 विद्यालयी शिक्षा पर एवं 1/3 उच्च शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सांदर्भिक उपादेयता बढ़ जाती है।

(घ) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के अधोलिखित तात्कालिक कमियों का उल्लेख किया था-

- माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम छात्रों की आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों के अनुरूप नहीं है। इसलिए छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है।
- शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम के प्रारूप के कारण छात्रों में सहयोग की भावना, आत्म सम्मान, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता जैसे गुणों का विकास छात्रों में नहीं होता है।
- माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली वैध एवं विश्वसनीय नहीं है इसलिए छात्रों की योग्यताओं, सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा का समुचित मूल्याँकन नहीं हो पाता है।
- माध्यमिक शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान केंद्रित है। इसमें जीवन संबंधी कार्यप्रणाली तथा समस्याओं का बोध नहीं कराया जाता है।
- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक-छात्र संबंध एवं अंत:क्रिया का अभाव होता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

– कक्षाओं में शिक्षक-छात्र अनुपात अव्यावहारिक होता है। शिक्षक अपने छात्रों को पहचान नहीं पाता है।
– शिक्षण वृत्ति आकर्षक नहीं है (शर्मा, 2006)।

(ङ) माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापन की शिक्षण विधि परंपरागत है। केवल पुस्तक प्रणाली अथवा व्याख्यान पद्धति का ही प्रचलन है अर्थात् माध्यमिक शिक्षा प्रणाली 'चाक एवं टाक' विधि तक ही सीमित है।

(च) परीक्षा केंद्रित माध्यमिक शिक्षा के कारण अनुचित साधनों का प्रयोग एक जीवन पद्धति बन गया है इसलिए यह शिक्षकों को चयनात्मक अध्यापन एवं छात्रों को चयनात्मक अध्ययन की तरफ अभिप्रेरित करती है। सूचना एवं उपाधि को ही शिक्षा के मूल उद्देश्य का पर्याय समझा जाने लगा है।

(छ) परीक्षा केंद्रित एवं सूचना केंद्रित होने के कारण माध्यमिक शिक्षा में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा का पूर्णत: अभाव है।

(ज) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य राज्यों द्वारा आयोजित बोर्ड द्वारा परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति में विषमता का समावेश होना।

(झ) शिक्षा की अवधारणा में परिवर्तन का होना। वर्तमान सूचना संचार युग में शिक्षा को एक 'वस्तु' माना जा रहा है, परिणामत: नैतिक मूल्यों के अभाव में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चरित्र निर्माण का स्थान धनार्जन ने ले लिया है। जिससे पूरे माध्यमिक शिक्षा तंत्र का अवमूल्यन हुआ है।

(ञ) माध्यमिक विद्यालयों में वित्तविहीन शिक्षा प्रणाली के कार्य संस्कृति के प्रभावी होने के कारण भी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में अप्रत्याशित रूप से संपूर्ण शैक्षिक पारिस्थितिकी में अवमूल्यन हुआ है क्योंकि शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करना व्यवसाय का पर्याय बन गया है।

(ट) माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली सिर्फ छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित है, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष पूर्णत: उपेक्षित हैं। इसलिए छात्रों में निर्णय शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन आदि पक्षों का विकास नहीं हो पाता है।

(ठ) माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में प्रचलित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया स्मृति के शिक्षण तक ही सीमित है। अवबोध, परावर्तन, विश्लेषण एवं संश्लेषण का पूर्णत: विलोप है अत: छात्रों को रटने पर बल मिलता है।

(ड) शिक्षक एवं छात्रों में अध्यापन एवं अध्ययन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण। इसके लिए शिक्षक का शिक्षण संस्था से अनुपस्थित होना एवं छात्रों का सिर्फ नामांकन एवं परीक्षा को ही शिक्षा का पर्याय मानना। उदाहरणार्थ, 10वीं कक्षा में शिक्षण संस्था में प्रवेश तो 1000 छात्रों का सैद्धांतिक रूप से है लेकिन कक्षा शिक्षण में कुल उपस्थिति लगभग 200 है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु माध्यमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एक

सकारात्मक दृष्टिकोण है। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अनुप्रयोगात्मक उपादेयता से इनकार नहीं किया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियों का अधोलिखित समाधान प्रस्तावित कर माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है।

(क) माध्यमिक शिक्षा में अनुचित साधन प्रयोग परीक्षा पूर्व, परीक्षाकालीन एवं परीक्षा पश्चात् नकलबद्ध की सार्वभौमिक प्रवृत्ति को अभिभावक, छात्र, शिक्षक एवं समुदाय के सकारात्मक एवं सक्रिय सहयोग से हतोत्साहित किया जाए एवं संपूर्ण शैक्षिक पारिस्थितिकी में कार्य संस्कृति विकसित किया जाए।

(ख) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को स्मृति स्तर (रटने पर ज़ोर) के शिक्षण से अवबोध स्तर के शिक्षण के तरफ उन्मुख किया जाए।

(ग) माध्यमिक शिक्षा की शिक्षण पद्धति को सिर्फ 'चाक एवं टाक' से सूचना एवं संचार तकनीक (ई-एजुकेशन, टीचिंग एवं लर्निंग) की तरफ प्रतिमान परिवर्तन किया जाए।

(घ) माध्यमिक शिक्षा को सिर्फ सूचनात्मक, सैद्धांतिक एवं संज्ञानात्मक न बनाकर इसे भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के समन्वित विकास हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

(ङ) माध्यमिक विद्यालयों से ट्यूशन एवं कोचिंग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर शिक्षक-छात्रों में कक्षा-शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं कार्य संस्कृति विकसित की जाए।

(च) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप-2005 के आलोक में अधोलिखित संस्तुतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए—
- मांग के अनुरूप परीक्षा का आयोजन।
- पास-फेल लिखने की जगह पुनर्परीक्षा वांछनीय।
- विद्यालय में सहायता एवं परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।
- पाठ-आधारित परीक्षा की जगह समस्या समाधान और क्षमता आधारित मूल्याँकन।
- सूचना को ज्ञान समझने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण।
- शिक्षकों के व्यावसायिक दक्षता में सुधार से संबंधित तथ्य सेवापूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण से संबंधित नीतियों में समाहित हो (एन.सी.एफ, 2005)।

(छ) माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षा पति में आमूल-चूल परिवर्तन करके 25-40% प्रश्न लघुउत्तरीय प्रकार के एवं शेष बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाहित कर छात्रों में तनाव को कम किया जाए।

(ज) माध्यमिक शिक्षा के लिए धन का आवंटन प्राथमिक शिक्षा की भाँति सुनिश्चित किया जाए क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान की भाँति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मकता से प्रत्यक्षत: संबंधित है।

संदर्भ

एन.सी.एफ., 2005. *एन.सी.ई.आर.टी.*, श्री अरविन्द मार्ग, नयी दिल्ली

तिलक, जे.बी.जी., 2004. *पब्लिक सबसिडीज इन एजुकेशन इन इंडिया*, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली

दि हिन्दू - *मूव टू यूनिवर्सलाइज सैकेंडरी एजूकेशन, 7 जुलाई 2008*

मीडिया मीमांसा - *विश्वविद्यालयों के बदलते परिसर,* माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल, वर्ष 2, अंक-1, जुलाई-सितंबर 2008

वू, किन बिंग, विनीता कौल, एंड दीपा शंकर, 2005. *हाऊ इण्डिया इज एचिविंग यूनिवर्सल इलीमेन्ट्री एजुकेशन*, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ए क्वाटरली मैगज़ीन ऑफ आई. एम.एफ., वा. 42, नं.-2

शर्मा, आर.ए., 2006. *भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास*, मेरठ, आर. लाल बुक डिपो